NAPM युवा संवाद

(संवाद, संघर्ष और संविधान को मजबूत करने की दिशा में)

https://napmyuvasamvad.wordpress.com/

महीने भर चले अभियान का सारांश

युवाओं का राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध: जुलाई 2021

राजनीतिक उत्पीड़न का सामना कर रहे सभी साथियों के साथ एकजुटता और मानवाधिकार रक्षक स्टेन स्वामी को दर्द और गर्व के साथ याद करते हुए

31 जुलाई, 2021: युवा संवाद एक ऑनलाइन मंच है जो विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक जन आंदोलनों का हिस्सा रहे या उनके साथ एकजुटता में काम करने वाले साथियों द्वारा संजोया गया है, जहां विभिन्न सामाजिक स्थितियों से आने वाले युवा साथी, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के संघर्ष को समझ सकते हैं, मज़बूती प्रदान कर सकते हैं। एनएपीएम युवा संवाद सामाजिक परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं और परिस्थितियों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य उन आंदोलनों और मुद्दों के बीच अधिक निरंतर और नियमित बातचीत स्थापित करना, सीखना और एकजुटता बनाना है जो हमारे लिए मायने रखते हैं।

मुद्दों पर और समुदायों के साथ प्रत्यक्ष ज़मीनी कार्य के अपार मूल्य को स्वीकार करते हुए, हम यह महसूस करते हैं कि वर्चुअल स्पेस में भी निरंतर जुड़ाव एक दूसरे को जानने, बंधनों को मजबूत करने, बातचीत से सीखने, एकजुटता बढ़ाने, मुद्दों को आवाज़ देने और दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए काम करने के लिए आवश्यक है। आज के समय में, ऑन-ग्राउंड और ऑन-लाइन दोनों राजनीतिक कार्य एक दूसरे के पूरक और मज़बूती प्रदान करने वाले हो सकते हैं। युवा संवाद के इतिहास, अवधारणा, उद्देश्यों आदि के बारे में यहाँ और पढ़ें।

दुनिया भर में दक्षिणपंथी शासनों के उदय ने अपराधीकरण, निगरानी, क़ैद और हिरासत में हिंसा के माध्यम से राज्य के दमन को तेज़ कर दिया है। मोदी, ट्रम्प, एर्दोगान जैसे नेताओं के राजनीतिक और वैचारिक प्रभावों का विरोध करने वाले युवाओं को लगातार राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। 'यंग इंडिया' - जैसा कि मोदी युवाओं को बुलाना पसंद करते हैं - ने प्रधान मंत्री के एक संपन्न और गौरवशाली "न्यू इंडिया" के वादों से आकर्षित होकर, भाजपा को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सत्तारूढ़ शासन इस तबके के भीतर असंतोष को संदेह और तिरस्कार के साथ देखता है, खासकर जब यह असंतोष मुस्लिम, दलित-बहुजन, आदिवासी और अन्य हाशिए के युवाओं द्वारा ज़ाहिर किया जाता है- वे लोग जो कभी भी भाजपा के सपनों के 'न्यू इंडिया' के निर्माण में समान भागीदार के रूप में नहीं देखे गए अगर वे उसके ब्राह्मणवादी एजेंडे के आगे नहीं झुके। राजनीतिक रूप से मुखर और सक्रिय महिलाएं और छात्र इस शासन की 'हिट लिस्ट' में शामिल प्रतीत होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, जिन युवा मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों ने अपनी शर्तों पर भारत में अपनी जगह की मांग की है, उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया गया है। गैर-अधिसूचित जनजातियों के युवा, ट्रांसजेंडर युवा, और 'संघर्ष क्षेत्रों' से आने वाले युवा- चाहे वह कश्मीर हो, "नक्सल बेल्ट" या उत्तर-पूर्वी राज्यों हों, को बेतरतीब ढंग से उठाया गया और क़ैद किया गया. यहाँ तक कि नियमित रूप से 'मुठभेड़' भी किया जाता रहा। इनमें से कुछ क्षेत्रों में राज्य और संरचनात्मक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे (जैसे, सीएए/एनआरसी), इसकी निरंकुश रूप

से कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां (जैसे कृषि कानून, श्रम कानून सुधार, ईआईए से छेड़छाड़), और इसके नरसंहार जैसे कोविड कुप्रबंधन के खिलाफ संघर्षों में नेतृत्व प्रदान करने वाले युवाओं पर जमकर निशाना साधा गया है। सवर्ण युवाओं, विशेषकर महिलाऐं, जिन्होंने उत्पीड़ितों का साथ देने का प्रयास किया है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है।

सभी उत्पीड़ित युवा नेता सरकार को तत्काल राजनीतिक चुनौतियाँ देने में नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इनमें से कई श्रम अधिकारों, विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, लिंग, जाति, मूलनिवासी अधिकारों और पर्यावरण के सवालों के इर्द-गिर्द आयोजन कर रहे हैं - वह राजनीति जो हिंदुत्व/कॉर्पोरेट शासन के लिए दीर्घकालिक वैचारिक चुनौतियां पेश करती है। इनमें से कुछ प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय (जैसे बंगाल और असम में प्रवास), कुछ राष्ट्रीय (जैसे कृषि और श्रम कानून), और अन्य बेहद स्थानीय हैं (जैसे भूमि अधिग्रहण)। इनमें से कुछ मुद्दे मोदी शासन (जैसे सीएए/एनआरसी) के दौरान उभरे हैं, जबकि अन्य की जड़ें असमानता, जाति, पितृसत्ता और भारत के संवैधानिक वादों की वास्तविक प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक संघर्षों में हैं। इस विविधता के बावजूद, ऐसे सभी आयोजन जिनके लिए युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्व और कॉर्पोरेट शासन के विरूद्ध एक विकल्प खड़ा करने की मंशा रखते हैं।

युवाओं के उत्पीड़न, और उनके अनुभवों के सार्वजनिक पुनर्वाचन ने इस क्रूर, अन्यायपूर्ण, और भेदभावपूर्ण क़ानूनी सिस्टम की आलोचना को मजबूत ही किया है। UAPA जैसे कठोर कानूनों के आह्वान और "दुरुपयोग" ने भारतीय क़ानून की अन्यायपूर्ण और अमानवीय संरचना, और इसकी पूर्ववर्तियों जैसे TADA, POTA या AFSPA के साथ-साथ देशद्रोह से संबंधित कानूनों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। महामारी के दौरान युवा राजनीतिक कैदियों की गिरफ्तारी ने लोगों को जेल की दयनीय स्थिति की झलक दिखाई , जबकि ट्रायल में लंबी देरी ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से कई दलित, मुस्लिम, आदिवासी, एनटी-डीएनटी, महिला और लैंगिक हाशिये से संबंधित हैं जिनके पास अक्सर कैदियों के बुनियादी अधिकारों तक पहुंचने के लिए कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने के संसाधनों की कमी होती है।

नोट्स, पत्र और साक्षात्कार जो हमें जेल के जीवन के बारे में बताते हैं, हमें जेल की स्मरण, इच्छा, दुःख, अफसोस, परित्याग और संकल्प की भावनाओं से समृद्ध स्थान के रूप में पुनर्कल्पना करने में मदद कर रहे हैं। हिंसा/बहादुरी के स्थान के रूप में जेल की पारंपरिक मर्दाना छवि से यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, जिसने जेल को लेकर हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब विश्व स्तर पर क़ैद को राष्ट्र-राज्यों द्वारा एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जब वे प्रवास से संबंधित मुद्दों (जैसे, असम एनआरसी), बेरोजगारी (अमेरिका में अश्वेत युवाओं की कैद), विस्थापन (जैसे रोहिंग्या) को अपने राजनीतिक और आर्थिक ढांचे के भीतर हल करने में असमर्थ दिखते हैं। जेल उन्मूलन एक ऐसा नारा है जो दुनिया भर में गूंजता हो और समय आ गया है कि भारत में भी कैद, निगरानी और कानूनी और हिरासत में हिंसा से संबंधित सवालों को राजनीति की मुख्यधारा में लाया जाए।

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का मानना है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और 'यंग इंडिया' के बीच की लड़ाई हमारे समय की एक प्रमुख राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें भारत के भविष्य को तय करने की क्षमता है, साथ ही कानून और जेल से जुड़े उन मुद्दों को मुखर करने की भी क्षमता है जिन्हें इस लड़ाई ने हमारे सामने लाया है। इसलिए, जुलाई के महीने में, हमने उन युवाओं को सुनने के लिए एक महीने का अभियान आयोजित किया, जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया है। हमने युवाओं के राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध के व्यापक विषय के तहत चार समर्पित सत्र आयोजित किए, जिसमें हमने विभिन्न सामाजिक स्थानों के युवा साथियों के साथ बातचीत की, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के राज्य दमन का सामना किया है और कई तरह से इसका विरोध कर रहे हैं।

जुलाई में निम्न विषयों *के संदर्भ में बातचीत हुई*

8 जुलाई
दमनकारी कानून और युवा
(यूएपीए, देशद्रोह और अन्य 'विशेष' कानून)

15 जुलाई
जेलों की परिस्थितियाँ एवं युवा
(सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जेल सुधार)

22 जुलाई
हाशिए पर खड़े युवाओं का नियोजित उत्पीडन
(वंचित पहचानें और संघर्षरत क्षेत्रों के साथी)

29 जुलाई
विभिन्न आन्दोलनों में शामिल युवाओं का राजकीय दमन और हमारा प्रतिरोध

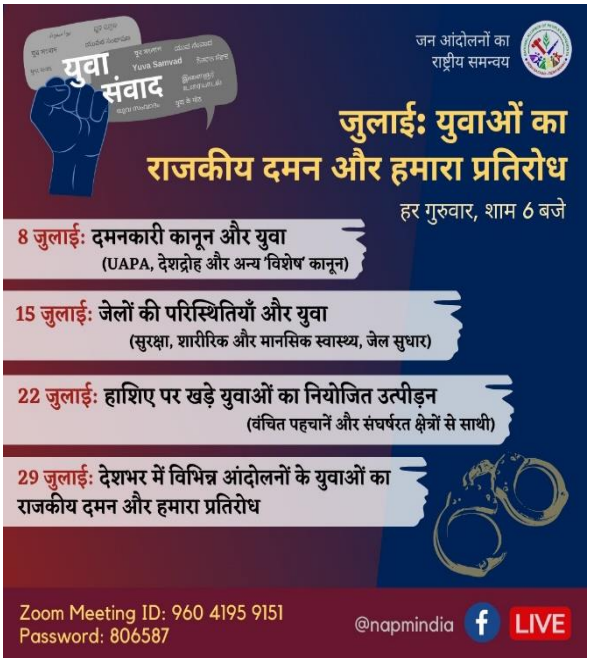

सभी सेशन यहाँ देखे जा सकते हैं: *https://napmyuvasamvad.wordpress.com/conversations/*

सोशल मीडिया अभियान: 15 से 31 जुलाई:

#FreeTheYoung

युवा संवाद टीम ने महीने भर के प्रयासों के तहत एक सोशल मीडिया अभियान का भी आयोजन किया, जिसका समापन 31 जुलाई को शाम 6 से 8 बजे तक एक ट्विटर स्टॉर्म के रूप में हुआ।

#FreeAllPolitical Prisoners

देश भर के कई युवाओं और विचारशील नागरिकों ने उपरोक्त हैशटैग का उपयोग करते हुए राजनीतिक क़ैदियों के साथ एकजुटता में तस्वीरें, कलाकृति, कविताएं, एकजुटता संदेश, खुद की तख्तियां पकड़े हुए चित्र पोस्ट किए।

पहला सेशन: 8 जुलाई 2021: दमनकारी कानून और युवा

(यूएपीए, देशद्रोह और अन्य 'विशेष' कानून)

ब्रिटिश सरकार द्वारा 'आपराधिक जनजातियों', 'सामाजिक पृथकों' और राजनीतिक असंतुष्टों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'विशेष क़ानूनों' की मृत्यु औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ नहीं हुई थी। राजद्रोह कानून, कुख्यात आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और अन्य क़ानून जो असहमति का अपराधीकरण करते हैं, स्वतंत्रता के बाद की कानूनी व्यवस्था की केंद्रीय विशेषताओं में रहे हैं।

बहुसंख्यकवाद और सुरक्षा राज्य के उदय ने टाडा, पोटा और बाद में यूएपीए के रूप में कई नए कानूनों को जनम दिया, जो अनिवार्य रूप से "आंतरिक अन्य" - दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों, के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त रूप से लचीले हैं, खासकर अगर वे 'अन्य' प्रतिरोधी, मानवाधिकार रक्षक या राजनीतिक विरोधी हों। अधिकांश राज्यों के अपने कानून भी हैं जो प्रकृति में दमनकारी हैं।

इस सत्र में हमने इनमें से कुछ कानूनों के तहत हाल के उत्पीड़न के अनुभवों को सुना, उनके तहत किए गए अन्यायों पर प्रकाश डाला, साथ ही अभियुक्तों, उनके दोस्तों और उनके परिवारों के जीवन पर उनके प्रभाव और इन क़ानूनों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने की चुनौतियों पर बात की।

वक्ता:

सिराज दत्ता, *सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड*

बातचीत में

मायशा, *छात्र, भिलाई, छत्तीसगढ़*
(सुधा भारद्वाज, जिन्हें भीमा कोरेगाव केस में गलत तरह से फंसा कर ३ साल से अधिक से जेल में क़ैद रखा गया है, की बेटी)

निहलसिंग बी राठौड़, *भीमा कोरेगांव मामले में बचाव पक्ष के वकील, नागपुर*

नताशा नरवाल, *नागरिकता कानून विरोधी कार्यकर्ता, पिंजरा तोड़, नई दिल्ली, 'दिल्ली दंगों' में झूठे तरीके से फँसायी और UAPA के तहत क़ैद की गयीं*

दूसरा सेशन:15 जुलाई: जेलों की परिस्थितियाँ एवं युवा

(सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भेदभाव, जेल सुधार)

भारतीय जेल लंबे समय से बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को रखने के लिए बदनाम रही हैं, अक्सर अत्यधिक भीड़भाड़ वाली, और कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जोखिम वाली परिस्थितियों में। इसके अतिरिक्त, अधिकांश कैदी हाशिए की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं और जेल के अंदर कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल और संसाधनों की कमी से ग्रसित होते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ उनका बहुत कम संपर्क हो पाता है। जेल प्रणाली उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डालती है।

हाल ही में कोविड महामारी और कई राजनीतिक कैदियों की पीड़ा, पैरोल और अंतरिम जमानत को लेकर कैदियों का अमानवीय वर्गीकरण, और एक उग्र महामारी और असंवेदनशील राज्य के सामने कैदियों की सरासर लाचारी, ने एक बार फिर से इस प्रणाली की क्रूरता को सामने लाया है।

यहां तक कि जेल नियमावली में लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का भी नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है और जेल हिंसा, भेदभाव और भ्रष्टाचार का एक दुर्गम स्थान रही हैं। इस सत्र में हाशिए के स्थानों से आते वक्ताओं ने इन मुद्दों में से कई को प्रभावी ढंग से उठाया, और जेल उन्मूलन की वैश्विक मांगों के साथ अपने अनुभवों को जोड़ते हुए, जेल सुधारों की एक शक्तिशाली मांग उठाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

वक्ता:

साई बौरोथु, *कॉमनवेल्थ मानवाधिकारों के लिए पहल, जेलों में बंद कुइर व्यक्तियों के लिए परियोजना, नई दिल्ली*

बातचीत में

शिव कुमार, *मज़दूर अधिकार कार्यकर्ता, मज़दूर अधिकार संगठन, हरियाणा, जेल और टॉर्चर का सामना किया*

सफूरा जरगर, *जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल की क्षात्र, नई दिल्ली. 'दिल्ली दंगो' में झूठे तरीके से फँसायी और UAPA के तहत क़ैद की गयीं*

हरिन तमसोय, *आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, चाईबासा, झारखंड, गलत तरीके से जेल किये गए*

तीसरा सेशन: 22 जुलाई: हाशिए पर खड़े युवाओं का नियोजित उत्पीडन

(वंचित पहचानें और संघर्षरत क्षेत्रों के साथी)

न केवल 'राजनीतिक कार्यकर्ताओं', बल्कि आम नागरिकों ने भी हाल के दिनों में भारी राज्य उत्पीड़न और सामाजिक प्रोफाइलिंग में वृद्धि का सामना किया है। "आतंक" का मुकाबला करने के बहाने, युवा मुस्लिम पुरुषों को नियमित रूप से पूरे देश में उठाया गया है, और मध्य और पूर्वी भारतीय राज्यों में हिंसक, कॉर्पोरेट समर्थक विकास के विरोध में खड़े युवा आदिवासियों को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। कश्मीर और उत्तर-पूर्व के सैन्यीकृत क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहां राज्य के दमन को थोड़ी सी भी चुनौती का जवाब क्रूर बल और दमनकारी कानूनों जैसे AFSPA और PSA से दिया जाता है।

इस तरह के हमले कारावास से आगे निकलते हुए न्यायेतर हत्याओं, जबरन गायब किया जाना , बलात्कार, यौन हिंसा और हिरासत में मौतों में भी बदले हैं। ये घटनाएं सत्तारूढ़ व्यवस्था की ब्राह्मणवादी प्रकृति की ओर इशारा करती हैं, जो मुस्लिम, दलित-बहुजन, आदिवासी, ट्रांसजेंडर, एनटी-डीएनटी और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को राज्य की नजर में तिरस्कृत समझती है -जो अपने अस्तित्व मात्र के लिए सताए जा सकते हैं और शासन में सुरक्षा राज्य के एकतरफा प्रयोगों के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं । इस सत्र में हमने हाशिए के युवाओं के अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा की और संगठन और एकजुटता के रूपों पर विचार किया जो हमें इसका मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।

वक्ता:

एविटा दास, *पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शहरी शोधकर्ता*

बातचीत में

रानी उर्फ़ राजेश, *ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मुम्बई, 1.5 साल गलत तरह से क़ैद*

आतिश इंद्रेकर छारा, *विमुक्त समाज कार्यकर्ता, बुधान थिएटर, गुजरात, गलत तरह से चार्ज और जेल किये गए*

थोकोचोम वीवोन, *छात्र कार्यकर्ता और शोधकर्ता, मणिपुर, देशद्रोह का आरोप लगाया गया*

कश्मीर से युवा साथी, *युवाओं के संघर्षों और प्रतिरोध पर परिपेक्ष्य*

चौथा सेशन: 29 जुलाई: विभिन्न आन्दोलनों में शामिल युवाओं का राजकीय दमन और हमारा प्रतिरोध

हाल के दिनों में हमने युवाओं को लक्षित करने में एक विशिष्ट पैटर्न देखा है। भारत भर में विविध आंदोलनों में शामिल युवाओं को कैद किया जा रहा है। इस तरह के आंदोलनों की सूची में सीएए / एनआरसी विरोधी आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, श्रम कानून में 'सुधार', ईआईए कमजोर करने, भूमि हड़पने और भूमि, जंगलों और तटों से बेदखल करने के विरुद्ध, एनईपी विरोधी और अन्य छात्र संघर्ष, जाति विरोधी और नारीवादी आंदोलन शामिल हैं। हालाँकि ये सभी आंदोलन अपने तरीके से हिंदुत्व/कॉर्पोरेट सत्तारूढ़ गठजोड़ के खिलाफ हैं, इन पर दमन अन्य युवाओं के लिए एक स्पष्ट संकेत है: 'राजनीति' से दूर रहो। दिलचस्प बात यह है कि यह राज्य दमन और अधिक युवाओं को राजनीतिक बना रहा है। इस सत्र में हम उन आंदोलनों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे जिनमें युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, और कानूनी सहायता, एकजुटता कार्य, देखभाल कार्य और भावनात्मक समर्थन सहित ऐसे दमन के प्रति प्रतिरोध के हमारे तरीकों पर चर्चा करेंगे।

वक्ता:

गुनीत कौर, *वकील व मानवाधिकार शोधकर्ता, पंजाब, पंजाब के युवाओं के दमन से जुड़े अनुभवों को भी साझा करते हुए बातचीत में*

सिकारी रोंगपि, *किसान व सामाजिक कार्यकर्ता, मीकिर बामुनी, असम, अज़्युर सोलर पावर के लिए ज़मीन हड़पने का विरोध करने के लिए क़ैद किये गए*

दिशा रवि, *पर्यावरण व जलवायु न्याय कार्यकर्ता, बैंगलोर, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गलत तरह से UAPA में फँसाई गयीं*

रवि आज़ाद, *युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा, किसान आंदोलन के साथ करने पर कई केस में फंसाये गए*

(उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से 2 साथियों के वक्तव्य)

हितेश्वरी, *पर्यावरण और मानवाधिकार आदिवासी कार्यकर्ता हिडमे मरकम की छोटी बहन*

सुरेश राठौर, *मनरेगा मज़दूर यूनियन और पूर्वांचल किसान यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिछले वर्ष उप्र पुलिस द्वारा बार बार हाउस अरेस्ट किये गए।*

हमने युवाओं के राजनीतिक रूप से संगठित होने और इस प्रक्रिया में राज्य दमन से निपटने की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया, साथ ही हमने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समर्थन और एकजुटता पर भी विचार किया जिसमें कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन शामिल हैं। इन चार सत्रों और बीच में एकजुटता अभियान के दौरान हमने गहन और बहुस्तरीय बातचीत करने की कोशिश की, जिससे हमें अलोकतांत्रिक कानूनी और हिंसक शासनों और राज्यों को चुनौती देने के लिए अधिक ऊर्जा और प्रेरणा मिली।

युवा संवाद के रूप में जारी बातचीत में हमारे साथ बने रहें

साप्ताहिक सत्रों के अधिक विवरण के लिए कृपया हमारे अपडेट और सोशल मीडिया पेजों का अनुसरण करें

युवा संवाद के पिछले सत्र देखें: https://napmyuvasamvad.wordpress.com/

प्रश्नों और प्रतिक्रिया के लिए कृपया बेझिझक हमें यहां लिखें: napmyuvasamvad@gmail.com

एकजुटता में,
एनएपीएम युवा संवाद टीम